मनरेगा योजना

चर्चा में क्यों ?

- केंद्र के नवीनतम आदेश के अनुसार केवल आधार-आधारित खातों के माध्यम से मनरेगा मजदूरी का भुगतान किया जयेगा जिसके तहत लगभग 57% सक्रिय श्रमिकों को योजना से बाहर कर दिया गया है।
- दूसरी और एक अन्य घोषणा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के लाभार्थियों पर मजदूरी का वित्तीय बोझ भी राज्य सरकारों द्वारा उठाया जाना चाहिए, ताकि भ्रष्टाचार को नियंत्रित किया जा सके क्योंकि MGNREGS को 14 राज्यों में केंद्र की बकाया राशि के रूप में 6,157 करोड़ रू. का नुकसान हुआ है।
- मनरेगा संघर्ष मोर्चा के छत्र निकाय के तहत काम करने वाले शिक्षाविदों और कार्यकर्त्ताओं ने मंत्रालय के नवीनतम आदेश पर चिंता व्यक्त की, जो मजदूरी के लिए आधार-आधारित भुगतान को अनिवार्य बनाता है।

मनरेगा के बारे में

- मनरेगा को "एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, जिसके लिए प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्यों को अकुशल मैनुअल काम करने के लिए शामिल किया गया था।"
- मनरेगा का एक और उद्देश्य है टिकाऊ संपत्तियों (जैसे- सड़कों, नहरों, तालाबों, कुओं) का निर्माण करना। इसके तहत किसी आवेदक के निवास के 5 किमी. की परिधि में रोजगार उपलब्ध कराया जाता है और उसे न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाता है।
- यदि आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर काम नहीं दिया जाता है, तो आवेदक बेरोजगारी भत्ता के हकदार होते हैं।
- मनरेगा के तहत रोजगार एक कानूनी अधिकार है।
- मनरेगा को मुख्य रूप से ग्राम पंचायत (GP) द्वारा लागू किया जाता है। इसमें ठेकेदारों की भागीदारी प्रतिबंधित है। इसके तहत जल संचयन, सूखा राहत और बाढ़ नियंत्रण के लिए आधारभूत संरचना बनाने जैसे श्रम-गहन कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है।

- मनरेगा को एक नियमित रोजगार योजना के रूप में नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि यह केवल उन लोगों के लिए एक फॉल-बैक तंत्र है, जिन्हें कहीं और रोजगार नहीं मिल सकता है।
- मनरेगा के लिए 2023-24 के केंद्रीय बजट आवंटन में पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में 33% की कटौती की गई है, वहीं दूसरी ओर सुझाव दिया गया कि केंद्र के 100% भुगतान की बजाय वेतन बिल का 60-40% के रूप में क्रमशः केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन किया जाना चाहिए।

आधार लिंक अनिवार्य क्यों ?

- वर्तमान में मनरेगा प्रणाली ने मजदूरी भुगतान के दो तरीकों की अनुमति दी थी: "खाता-आधारित" या "आधार-आधारित" मजदूरी का भुगतान सीधे श्रमिकों के खातों में किया जाता है, परंतु मंत्रालय ने 1 फरवरी से प्रभावी वेतन भुगतान के तरीके में बदलाव का आदेश जारी किया।
- काम करने के लिए आधार-आधारित विकल्प के लिए, न केवल कार्यकर्त्ता के जॉब कार्ड और बैंक खाते को आधार से जोड़ा जाना चाहिए, बल्कि खाता भी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम से जुड़ा होना चाहिए।

प्रभाव

- सामाजिक दायरा कम होगा तथा 57% श्रमिकों को लाभ से वंचित कर दिया जायेगा।
- यह प्रक्रिया बहुत बोझिल हो सकती है क्योंकि इसके लिए कड़ी KYC आवश्यकताओं को पूरा करने की आवश्यकता होती है।
- 'कृत्रिम रूप से मांग कम करना' अर्थात एक मोबाइल-आधारित ऐप के माध्यम से उपस्थिति डेटा पर कब्जा करने का आदेश योजना के तहत काम की मांग को स्वचालित रूप से कम कर देगा।

राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव (आदि महोत्सव)

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा दिल्ली स्थित मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में मेगा राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव (आदि महोत्सव) का उद्घाटन किया गया।

आदि महोत्सव के बारे में

- आदि महोत्सव राष्ट्रीय मंच पर जनजातीय संस्कृति को प्रदर्शित करने का एक प्रयास है। इसके तहत जनजातीय संस्कृति, शिल्प, खान-पान, वाणिज्य और पारंपरिक कला की भावना का उत्सव मनाया जाता है।
- यह जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ लिमिटेड (ट्राइफेड) की वार्षिक पहल है।
- इसके तहत 3,000 से अधिक **वन-धन विकास केंद्रों**, 80 लाख **स्वयं सहायता समूहों** की स्थापना, विगत वर्षों में जनजातीय कल्याण के लिए बजट में वृद्धि का उल्लेख किया गया।

- आदिवासी बच्चों के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों को बढ़ावा देना और सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदे जाने वाले वन उत्पादों की संख्या में वृद्धि की भी चर्चा की गयी।
- आदि महोत्सव 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की संकल्पना को बढ़ावा देता है।
- आदि महोत्सव भारत की विविधता में एकता को शक्ति देता है तथा साथ में विरासत को मद्देनजर रखते हुए विकास के विचार को गति देता है।

आदिवासियों के लिए पहल

- भारत के जनजातीय उत्पादों की मांग बढ़ने के कारण इनका विदेशों में निर्यात बढ़ रहा है और इनमें बांस के उत्पाद भी शामिल हैं।
- पूर्व कानूनों के अनुसार बांस काटना और उसका उपयोग प्रतिबंधित था। जिसे बाद में घास की श्रेणी में लाया गया और सभी प्रतिबंधों को हटा दिया गया।
- भारत, जनजातीय जीवन शैली में ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं का समाधान बताता है। भारत के जनजातीय समुदाय के पास सतत विकास के संबंध में प्रेरित करने और सिखाने के लिए बहुत कुछ है।
- जनजातीय युवाओं को ध्यान में रखकर जनजातीय कलाओं और कौशल विकास को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस वर्ष के बजट में **पीएम विशवकर्मा योजना** को पारंपरिक शिल्पकारों के लिये शुरू किया गया है, जहाँ कौशल विकास तथा अपने उत्पादों को बाजार में बेचने के लिये समर्थन देने के अलावा आर्थिक सहायता भी दी जायेगी।
- बजट में अनुसूचित जनजातियों के लिए किये जाने वाले प्रावधान में भी 2014 की तुलना में पांच गुना वृद्धि की गई है।
- 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' का नारा देश के दूर-दराज के क्षेत्रों के हर नागरिक तक पहुंच रहा है। यह आदि और आधुनिक (आधुनिकता) के संगम की ध्वनि है, जिस पर नए भारत की शानदार इमारत खड़ी होगी।
- "पहली बार, देश ने भगवान बिरसा मुंडा की जन्म-जयंती पर 'जनजातीय गौरव दिवस' मनाने की शुरूआत की है।" झारखंड के रांची में भगवान बिरसा मुंडा को समर्पित संग्रहालय का उद्घाटन करने के अवसर प्रधानमंत्री द्वारा कहा गया था कि विभिन्न राज्यों में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित संग्रहालय बनाए जायेंगे।

स्रोत - PIB

ट्रेडिंग में वायदा और विकल्प (F&O) अनुबंध

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने स्थानीय हेज फंडों से अपने वायदा और विकल्प (F&O) ट्रेडों और अंतर्निहित शेयरों की घोषणा करने के लिए कहा है, जिन पर ऐसी इक्विटी डेरिवेटिव पोजीशन बनाई गई थी।

फ्यूचर्स एंड ऑप्शन (F&O) अनुबंध के बारे में:

- **फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट:** यह खरीददार और विक्रेता के बीच भविष्य में एक निश्चित समय पर एक निश्चित कीमत पर संपत्ति खरीदने या बेचने का एक समझौता है।
- समाप्ति तिथि पर मौजूदा बाजार मूल्य की परवाह किए बिना, खरीददार को खरीद या विक्रेता को निर्धारित मूल्य पर अंतर्निहित संपत्ति को बेचना चाहिए।
- अंतर्निहित संपत्तियों में भौतिक वस्तुएं और वित्तीय साधन (स्टॉक, मुद्राएं और बॉन्ड इत्यादि) शामिल हैं। ये उच्च जोखिम के अधीन हैं जिससे असीमित लाभ या हानि हो सकती है।
- **विकल्प अनुबंध:** एक विकल्प एक अनुबंध है जो एक निवेशक को भविष्य की एक निर्दिष्ट तारीख पर एक निर्दिष्ट मूल्य पर एक वस्तु खरीदने या बेचने का दायित्व नहीं, बल्कि अधिकार देता है।
- ये सीमित जोखिम उठाते हैं और असीमित लाभ या हानि प्राप्त कर सकते हैं।
- विकल्प अनुबंधों में प्रीमियम के रूप में अग्रिम भुगतान किया जाता है।

स्रोत - IET

थायरस नरेंद्रानी

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में, केरल के शोधकर्त्ताओं ने कोले आद्रभूमि से एक कोयल मधुमक्खी की एक नई प्रजाति की खोज की है और इसका नाम थायरस नरेंद्रानी रखा है।

थायरस नरेंद्रानी के बारे में:

- यह नई प्रजाति हाइमनोप्टेरा गण के एपिडे परिवार से संबंधित है।
- जीनस थाइरियस में कोयल मधुमक्खियाँ या क्लेप्टोपैरासिटिक मधुमक्खियाँ होती हैं।
- कोयल मधुमक्खियां अन्य मधुमक्खियों के घोंसलों को तोड़कर, उनमें घुसकर और अंडे देती हैं।

- अन्य मादा मधुमक्खियों के विपरीत, कोयल मधुमक्खियों में पराग-संग्रह करने वाली संरचना नहीं होती हैं।
- एक बार जब कोयल मधुमक्खी का लार्वा मेज़बान मधुमक्खी के घोंसले में से निकल जाता है, तो वह अपने बढ़ते हुए लार्वा के लिए मेज़बान द्वारा रखे गए भोजन को खा जाती है।

कोले आर्द्रभूमि के बारे में

- यह केरल के त्रिशूर ज़िले में स्थित है।
- इस क्षेत्र में चावल का अच्छा उत्पादन होता है तथा यह आर्द्रभूमि प्राकृतिक जल निकासी प्रणाली के रूप में कार्य करती है।
- यह वेम्बनाड-कोले आर्द्रभूमि **(Vembanad-Kole wetlands)** का एक हिस्सा है, जिसे रामसर कन्वेंशन के तहत आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- यहाँ अनेक प्रकार की आक्रामक प्रजातियाँ पाई जाती हैं।

रामसर अभिसमय

- यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों, विशेषकर जलप्रवाही पशु पक्षियों के प्राकृतिक आवास से संबंधित एक अभिसमय है। यह आर्द्रभूमियों के धारणीय प्रयोग और संरक्षण को सुनिश्चित करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है।
- हर साल **2 फरवरी** को पूरे विश्व में 'विश्व आर्द्रभूमि दिवस' (World Wetland Day) मनाया जाता है।

प्राथमिक कृषि साख समितियां (PACS)

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पांच वर्षों में 2 लाख पंचायतों में नई प्राथमिक कृषि साख समितियों की स्थापना को मंजूरी दी है।

प्राथमिक कृषि साख समितियां (PACS)

- PACS ग्राम-स्तरीय सहकारी ऋण समितियाँ हैं जो राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंकों (SCB) की अध्यक्षता वाली त्रि-स्तरीय सहकारी ऋण संरचना में अंतिम कड़ी के रूप में कार्य करती हैं।
- SCB से क्रेडिट जिला स्तर पर संचालित जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCB) को हस्तांतरित किया जाता है। DCCBs, PACS के साथ काम करती हैं, जो सीधे किसानों से संबंधित हैं।
- व्यक्तिगत किसान PACS के सदस्य होते हैं और उनके भीतर से पदाधिकारी चुने जाते हैं।

उद्देश्य-

- विभिन्न कृषि उद्देश्यों के लिए किसानों को लघु और मध्यम अवधि के ऋण प्रदान करना।
- अपने सदस्यों की समय पर मदद करने के लिए केंद्रीय वित्तीय एजेंसियों से पर्याप्त धन उधार लेना।
- कृषि प्रयोजनों के लिए किराए पर ली गई प्रकाश मशीनरी की आपूर्ति को बनाए रखना।
- अपने सदस्यों के बीच बचत की आदतों को बढ़ावा देना।
- कृषि आदानों की आपूर्ति की व्यवस्था करना।
- सदस्यों को विपणन सुविधाएं प्रदान करना, जिससे उचित मूल्य पर बाजार में उनके कृषि उत्पादों की बिक्री में वृद्धि हो सके।

स्रोत– IE

KARMANYEVADHIKARASTE
THE STUDY
MAA PHALESHU KADAACHAN
An Institute for IAS